special thrust in Gujarat, with emphasis on the following :

(i) Raising village wood lots,

(ii) Rehabilitation of degraded forests,

(iii) Raising plantations on malki lands,

(iv) Rehabilitation of degraded farm lands,

(v) Free supply of seedlings,

(vi) Motivating school children to raise seedlings in school compounds for purchase by the Forest Department.

Sale of Rehabilitation Residential Lease Properties

8428. SHRI DAYA RAM SHAKYA :
SHRI SATISH AGARWAL :
Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 345 on 27 February, 1984 regarding rehabilitation residential leases in Delhi colonies and state :

(a) the number of plots/houses in each colony listed in annexure to above noted question that have changed hands from the original allottee/leasee ;

(b) whether permission of sale was given in favour of dis-placed persons only ; and

(c) whether unearned increase in first or subsequent sales was payable to the Government for these different sized plots in each colony ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) No such data has been maintained.

(b) The question of giving sale permission is considered on the specific request of the lessee irrespective of whether he is a displaced person or not.

(c) Government's share of unearned increase is recovered from the lessee on the basis of provision in the Lease Deed irrespective of the size of the plot. No provision exists in the Rehabilitation Residential Leases for recovery of unearned increase in the first sale.

Setting up of National Agro-Industries Corporation.

8429. SHRI MOHANLAL PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Central Government are considering to set up a National Agro-Industries Coporation ; if so, the main function of the said corporation ;

(b) whether the State Governments have been asked to propose suitable projects which might be undertaken by the said National Agro-Industries Corporation ; and

(c) if so, what has been their response and by when the said Corporation is likely to be set up ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) The Central Government have appointed an Expert Committee to examine, inter-alia, the question of setting up of a National Agro-Industries Corporation. The Committee's report is awaited.

(b) No, Sir.

(c) Question does not arise.

उत्तर प्रदेश के नगरों को वित्तीय सहायता

8430 **श्री हरीश रावत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम और छोटे शहरों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगरों को वित्तीय सहायता दी गई और उन्हें कुल कितनी राशि दी गई;

(ख) 1984-85 वर्ष के दौरान सरकार का विचार कितनी राशि देने का है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय बाल्मिकी आवासीय ब्लाक के निर्माण के लिए अल्मोड़ा नगर की नगर पालिका को विशेष वित्तीय सहायता देगा; और

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत अनुमोदित शहरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई निधियां

(लाख रुपयों में)

राज्य	शहर	स्वीकृति की तारीख	दी गई केन्द्रीय सहायता					अनुमोदित परि- व्यय	राज्य क्षेत्र / परिव्यय	टिप्पणी
			1979-80	80-81	81-82	82-83	83-84			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
उत्तर प्रदेश (23)										
1.	जौनपुर	1-3-80	2.55	—	—	—	—	—	—	
		25-3-83	—	—	—	8.00	10.00	35.26	2.40	
2.	फतेहपुर	15-3-80	3.00	—	—	—	—	—	37.85	
		25-3-83	—	—	—	9.00	—	87.51	—	
		11-4-83	—	—	—	—	9.00	—	—	
3.	आजम गढ़	25-3-80	5.00	—	—	—	18.00	70.40	3.90	
4.	हाथरस	2-2-81	—	10.00	—	—	—	84.78	45.00	
5.	बांदा	2-2-81	—	4.00	—	—	—	—	—	
		25-3-83	—	—	—	9.00	—	63.51	31.92	
		11-4-83	—	—	—	—	9.00	—	—	
6.	बाराबंकी	26-2-81	—	8.00	—	—	—	66.83	5.09	
7.	रायबरेली	26-2-81	—	20.00	—	—	—	115.96	71.44	

8 अल्मोडा	16-3-81	—	2 00	—	—	—	—	1`0.40
	25-3-83	—	—	—	5.00	—	112.08	—
	11-4-83	—	—	—	—	8 00	—	—
9 एटा	16-3-81	—	1 50	—	—	—	—	उपलब्ध नहीं
	25-3-83	—	—	—	9.00	—	89.26	—
	11-4-83	—	—	—	—	11.00	—	—
10 बलिया	16-3-81	—	12.50	—	—	18.00	116.73	115.35
11. मोहब्बा	16-3-81	—	8.20	—	—	—	70.32	27 44
12. कासगंज	24-3-81	—	7.00	—	—	—	147.31	86.28
13. गाजीपुर	24-3-81	—	17.60	—	—	—	128.55	17.00
14. सीतापुर	24-3-81	—	15.00	—	—	—	133.27	103.32
15. मणिपुर	24.3.81	—	10.00	—	—	15 00	98.15	125 00
16. हरदोई	24.3.81	—	16.00	—	—	—	87.95	95.38
17. बिजनौर	24.3.81	—	4.75	—	—	16.00	47.71	उपलब्ध नहीं
18. ओराई	24.3.81	—	10.50	—	—	14.00	76.95	24.50
19. देवरिया	24.3.81	—	14.50	—	—	—	77.44	13.70
20. बदायु	27.11.81	—	—	13.00	—	—	260.03	22.03
21. अमेठी	24.3.82	—	—	6.00	—	—	40.86	12.16
22. काशीपुर	24.3.82	—	—	10.00	—	—	115.25	उपलब्ध नहीं
23. पडरोना	5.10.82	—	—	* 2.00	15.00	—	96.11	12.81 * कम लिया गया है
		10.55	161.55	31.00	59.00	128.00	2222.27	1022.96

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अनुमोदित शहरों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक दी गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्य सरकार को दी जाने वाली राशि, चालू योजनाओं के सम्बन्ध में निधियों के उपयोग की प्रगति पर निर्भर करेगी।

(ग) इस मन्त्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा शहर के लिए दो रिहायशी योजनायें है नामतः (I) राजपुरा ट्रेनिंग ग्राउण्ड में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग आवास योजना जिसकी लागत 4.40 लाख रुपए है और (II) 28.80 लाख रुपए लागत की खयारी रिहायशी योजना। इन दो रिहायशी योजनाओं के अलावा राज्य सरकार द्वारा कोई दूसरी रिहायशी योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

किसानों को कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराना

8431. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसलों की बीमारी की रोकथाम के लिए किसानों को कीटनाशक दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है, और यदि ये उपलब्ध कराई भी जाती हैं, तो उन्हें इसका अत्यधिक मूल्य चुकाना पड़ता है तथा यह स्थिति, विशेष रूप से जालोर और सिरोही जिला में बनी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कीटनाशक दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) देश में कीटनाशी औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता है और जालोर और सिरोही सहित देश के किसी भी भाग से किसी कीटनाशी औषधि की कमी होने की सूचना नहीं मिली है। कीटनाशी औषधियों के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। इन के मूल्य कच्चे माल की लागत, उत्पादन लागत, सरकारी लेवी आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करते हैं। तथापि, भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कीटनाशी औषधियों की लागत पर विभिन्न दरों पर राजसहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

Packing of Vegetable Ghee in Small Pack by DCM

8432. SHRI MANOHAR LAL SAINI : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether Delhi Cloth Mill Chemicals has packed more vegetable ghee in small packs than bigger packs of 16.5 kg. from 15 March, 1984 onwards ;

(b) if so, how many tins were packed of 16.5 kg and small packs, giving break-up of each size and how much was packed during the corresponding last three months ;

(c) whether the embargo placed on the DCM Chemicals to pack limited number of small packs is enforced and maintained and; has the Department of Civil Supplies made any checks as to whether the embargo is being maintained and will a report to that effect be laid on the Table of the House; and

(d) whether the recent port strike contributed to the shortage of 16.5 kg tins of Panghat in Delhi ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. MS